



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126467

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 14074 वर्ष 2026

कयामुद्दीन उर्फ कयामू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : दिनेश कुमार गुप्ता, राघवेन्द्र सिंह, रजनीश शुक्ला

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-विपक्षी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री ज्ञान बहादुर पटेल को सुना।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 04 वर्ष 2026, धारा 305(घ), 331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- सुखपुरा, जिला - बलिया के अंतर्गत जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ है और विलंब के संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है; कि आवेदक के कब्जे से कुछ चोरी की गई वस्तुओं की झूठी बरामदगी दिखाई गई है; आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है; कथित बरामदगी ज्ञापन का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है; जमानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर संख्या 20 से 23 में आवेदक के आपराधिक इतिहास को उचित रूप

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से स्पष्ट किया गया है। यह कहा गया है कि मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का संज्ञान लेने के पश्चात, सह-अभियुक्त, नामतः पथरू उर्फ पतरू नट को इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 16114 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 26.5.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। तदनुसार, आवेदक भी जमानत का हकदार है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी कोई आशंका नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के उपरांत, आवेदक विधि की प्रक्रिया से भाग जाएगा या अन्यथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा तथा आवेदक दिनांक 15.1.2026 से जेल में निरुद्ध है और निकट भविष्य में विचारण के समाप्त होने की संभावना बहुत क्षीण है।

4. तथापि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु उन्होंने अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं किया।
5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पत्रावली का अवलोकन करते हुए तथा आरोपों की प्रकृति, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत प्रदान करने हेतु एक उपयुक्त मामला पाती हूँ।
6. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक - कयामुद्दीन उर्फ कयामू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) और उसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां (जमानतें) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र (शपथ पत्र) प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
 - (ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्थिति में, विचारण न्यायालय आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय आवेदक के विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करेगा।

(iv) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ होने, (ii) आरोप तय होने और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और आवेदक के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

7. उपरोक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन को जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और विद्वान अवर न्यायालय जमानत निरस्त करने के संबंध में मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
8. जमानत प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

9 जून, 2026

वंदना वाई.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।